समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–

महाकौशल–संदेश

RNI No. MPHIN/2001/11140

वर्षः– 17 पृष्ठः– 4 अंक :– 24 संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा

यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

क्या टूट की कगार पर है पाकिस्तान ?

डॉ. किशन कछवाहा

पाकिस्तान में गत 70 वर्षो कें इतिहास में सभी 18 प्रधान मंत्रियों को उनका कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही उन्हें अपने पद से हटने को मजबूर कर दिया गया। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स लीक मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित कर दिया परिणाम स्वरूप उन्हें भी इस्तीफा देने को वाध्य होना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरूद्ध अभी एक और रिव्यू पिटीशन पेश की है जिसमे कोर्ट से अपने फैसले को वापिस लेने कहा गया है। पूर्व प्रधान मंत्री ने यह भी आशंका जाहिर की है कि कही पाकिस्तान का हश्र सन 71 जैसा ही न हो। उस समय पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बॅगला देश) अलग हो गया था। इस आशंका को राजनैतिक गलियारों में गंभीरता से लिया जा रहा है। वर्तमान हालातों में अमेरिका द्वारा भी पाकिस्तान को लगातार चेतावनी दी जा रही है। इसकी अनदेखी करते हुये वह चीन से अपने समबन्धों को मजबूत करने की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। प्रश्न यह उठता है कि नवाज शरीफ की इस आशंका में कितनी दम है या इसके पीछे कुर्सी चले जाने से उपजा आक्रोश मात्र है। कही ऐसा तो नही कि पाकिस्तान में इन दिनों जो परिस्थितियॉ उत्पन्न हुयी है, जिनके चलते उन्हे ऐसी आशंका व्यक्त करना पड़ी है। नवाज शरीफ नें गत स्प्ताह चेतावनी देते हुये यह भी कहा था कि अगर जनादेश का सम्मान नही किया गया तो पकिस्तान सन् 71 की तरह टूट जायेगा। ऐसी आशंका उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट द्वारा दिये गये उस फैसले के बाद जताई थी जिसमें शरीफ परिवार और उनकी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ की जा रही टिप्पणियों के प्रसारण पर रोक लगायी थी। नवाज शरीफ ने पनामा पेपर्स मामले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जॉच में देश की खुफिया एजेंसियों के हिस्सा बनने की भी वकीलों के एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये, आलोचना की थी। नवाज शरीफ ने कहा था कि देश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब आई.एस.आई और मिलिटरी इन्टेलीजेंस के प्रतिनिधियों को ऐसे मामले में जॉच के लिये ज्वाईंट इन्वेस्टीगेशन का हिस्सा बनाया गया। यह मामला न तो आतंक से जुड़ा था और न ही इसका राष्ट्रीय सुरक्षा से कुछ लेना देना था। ऐसी ही आशंका लगभग 18 साल पहले अमेरिका के थिंकटेंक द्वारा व्यक्त की गयी थी कि सन् 2020 तक दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामोनिशान मिट जायेगा। अमेरिकी थिंक टेंक ने सन् 1999 में एक पन्द्रह सदस्यीय टीम चेयरमेन हिक्स एंड एसोसियेट्स के.एस एंड विम्बुश से दिम्बुश के नेतृत्व में गठित की थी। उसमे अमेरिका के वुद्धिजीवी, शोधकर्त्ता, वैज्ञानिक, और प्रोसेसर सम्मिलित थे। इस टीम को नीति निर्धारण के लिये दीर्धकालिक नजारिया प्रस्तुत करने के लिये निर्देश दिये गये थे जिसके आधार पर भाविष्य की योजनाये तय की जा सकें। इस टीम ने 25 जुलाई से 4 अगस्त 1999 के बीच न्यूपोर्ट के नेबलवार कालेज में अपना विचार विमर्श किया। उस समय तैयार की गयी रिपोर्ट में चीन को एक बड़ी ताकत के रूप में देखा गया था। रिपोर्ट के प्रथम सिनोरियों में कहा गया था कि सन् 2010 तक पाकिस्तान की सारी व्यवस्था गल–सड़ जावेगी। घरेलू कलह, आर्थिक तंगी तथा सरकार की असहाय स्थिति इस देश के पतन का कारण होगी। शीध्र ही पंजाबी बगावत सिर उठायेगी जिसका हिस्सा, सिन्धी, बलूच और पठान बनेंगे। गली–गली में मुहाजिदो का आधिपत्य होगा। जबकि दूसरी तरफ भारत में आश्चर्यजनक गठजोड़ सामने आयेंगे और आर्थिक सुधारों की दिशा में काम होगा। चीन की बढ़ती ताकत अमरिका को भारत के नजदीक लायेगी। अमेरिका को भारत की रक्षा के लिये आगे आना होगा। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आण्विक ताकत इस्तेमाल करने का प्रयास करेगा। लेकिन अमेरिका उसके सभी ढिकानों को तहस–नहस कर देगा। कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान को पराजय का मुँह देखना पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का दक्षिण ऐशिया से नामोनिशान मिट जाना संभावित है और वह भारत का हिस्सा होगा। महर्षि अरविन्द ने भी अखण्ड भारत' की भविष्य वाणी कि थी। उन्होने कहा था कि भारत की आत्मा को जब तक एकता और अखण्डता प्राप्त नही हो जाती तब–तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी है, अपंग और अर्थहीन बनी रहेगी। उधर पाकिस्तान के चारों प्रान्तों में पंजाब के बर्चस्व और जन जातीय विभाजन में फाल्टलाईन और सिन्ध के पुराने आन्दोलन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में देश को बॉधने वाला सूत्र नही है। उसकी ऐकता का एक सूत्र भारत विरोध व धर्मान्धता को लगातार हवा देना रहा है दूसरा हिंसा और आतंकवाद का पोषक और निर्यातक पाकिस्तान गत अनेक वर्षो से अतिरेकी हादसों और विस्फोटों का स्वयं शिकार बना हुआ है। इस कारण कराची और उत्तर–पश्चिम के कुछ शहरों को आज दुनिया के सर्वाधिक ज्वलन शीन और खतरनाक स्थानों में गिना जा रहा है। इन कारणों से अमेरिका सहित कुछ पश्चिमी देशों के सुरक्षा विशेषज्ञ एवं विश्लेषक उसके अस्तित्व की संदिग्धता पर प्रश्न खड़ा करने लगे है। इसकी कार गुजारियों से अंतराष्ट्रीय समुदाय की चिन्ता बढ़ने लगी है। पाकिस्तान में सिर्फ सुन्नी मुसलमानों के हितों के लिये हिंसक वाददातों को अंजाम दिया जाता रहा है जिसके कारण सिन्धी, बलूची एवं अन्य अल्प संख्यक समुदाय ने पीडा ही पीड़ा झेली है। शिया, उक्करवाल, सिख, गुर्जर, व पंडितो को कुचलते रहने की कोशिशें होती रही। इस कारण पाकिस्तान में असन्तोष चरम पर है। दूसरी ओर इस्लामिक स्टेटअब इसका लाभ उठाकर पाकिस्तान को अपने चंगुल में फॅसाना चाहता है। इसभूमि पर कब्जे की जंग भी शुरू हो गयी है। हाल ही में लालशाहबाज कलंदर की दरगाह पर जो हमला, हुआ उसका यही संदेश है। पाकिस्तान इस सच्चाई को जानता है। सेना ने अफगानिस्तान की सीमा पर हमला बोल दिया है, लाखो के ढ़ेर लगाये जा रहे है। अफगानिस्तान की सीमा को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद की सड़कों पर सेना गश्त लगाने लग गयी है। पाकिस्तान में पहले से ही जिहादियों की फौज मौजूद है जो सत्ता से दूर है। अब वो बगदादी की सहायता से सत्ता पर काबिज हो जाय, उस पर किसी को हैरत नही होनी चाहिये। तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की 97 फीसदी आबादी मुस्लिम तो है लेकिन वह भी 70 टुकड़ो में बॅटी है। साथ ही साक्षरता की दर बहुत कम है। गरीब और आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या के उच्च घनत्व से नयी–नयी कठिनाईयॉ

शेष पृष्ठ क्रमांक 4 पर

'इस्लामिस्तान' में हिन्दू दमन

इस्लामिस्तान यानी पाकिस्तान में हिन्दुओं का लगातार दमन हो रहा है। यह बात पांथिक स्वतंत्रता से जुड़ी एक अमेरिका समिति ने कही है। यही वजह है कि वहां अब एक प्रतिशत भी हिन्दू नहीं बचे हैं।

पांथिक स्वतंत्रता वैश्विक स्तर पर एक अधिकार के तौर पर स्थापित हो गई है। सभी अंतराष्ट्रीय संस्थान तथा राष्ट्र कमोबेश इस स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं और दावा करते हैं कि उनके देश में पांथिक स्वतंत्रता पर्याप्त रूप में उपलब्ध है तथा इसको संवैधानिक संरक्षण भी उपलब्ध है। यह बात सच भी है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा पांथिक स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित तथा संरक्षित करती है। लेकिन अंतराष्ट्रीय स्तर पर पांथिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। जबरन कन्वर्जन, उपासना स्थलों पर हमले, निर्दोष लोगों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पर लगातार चुप्पी साधे हुए है। हाल ही में अमेरिका की अंतराराष्ट्रीय पांथिक स्वतंत्रता समिति ने मजहबी स्वतंत्रता पर मंडराते खतरों को चिह्नित किया है। थॉमस जे. रेसी की अध्यक्षता में लिखी 221 पन्नों की यह रपट दुनिया के देशों को तीन श्रेणी में विभाजित करती है। पहली श्रेणी में उन देशों को रखा गया है, जहॉ स्थितियां ज्यादा संवेदनशील हैं। इसे सीपीसी यानी 'कंट्रीज ऑज पर्टिकुलर कंसर्न' कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान के साथ म्यांमार,चीन, ईरान, सूडान तथा सीरिया सहित 16 'देश शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में बांग्लादेश, इथियोपिया, सोमालिया सहित नौ देश शामिल है। इस रपट में हिन्दू शब्द 147 बार, मुस्लिम 585 बार, ईसाई 324 बार, यहूदी 76 बार और बौद्ध 75 बार आया है। रपट में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दू समाज पर हो रहे अत्याचारों पर एक अध्याय है। रपट के अनुसार पांथिक अधिकारों पर लगातार हो रहे हमलों को पाकिस्तान सरकार रोकने के बजाए बढ़ावा दे रही है। मजहब के आधार पर भेदभाव, ईशनिंदा तथा अहमदिय विरोधी कानून मजहबी अल्पसंख्यकों की स्थिति को दयनीय बना रहा है। रपट के अनुसार पाकिस्तान में हिन्दू लगातार मंजहबी हिंसा का शिकार हो रहे हैं। आतंकवादी संगठन और अन्य शरारती तत्व हिन्दुओं पर निरंतर अत्याचार कर रहें हैं। रपट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकें लगातार गैर–मुस्लिमों के प्रति दुर्भावना और अन्य समुदायों के प्रति शक को बढ़ावा देती हैं तथा अन्य मत–पंथों को गलत रूप में प्रस्तुत करती हैं। इन पुस्तकों में पाकिस्तानी हिन्दुओं को भारत–परस्त और ईसाइयों को अमेरिका–परस्त बताया गया है। भारत को तो दुश्मन देश की श्रेणी में रखा गया है। इन बातों से उन्मादियों का हौसला बढ़ता है। रपट में हिन्दू तथा ईसाई लड़कियों का जबरन कन्वर्जन कराने और उनका निकाह किसी मुसलमान के साथ करा देने पर चिंता व्यक्त की गई है। रपट में यह भी बताया गया है कि हर वर्ष लगभग 1,000 हिन्दू और ईसाई लड़कियों का जबरन कन्वर्जन कराकर निकाह कराया जाता है। रपट यह भी कहती है कि जबरन मुसलमान बनाई गई लड़कियों को कोई भी कानूनी सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। विदित हो कि अमेरिका की यह समिति 2002 से पाकिस्तान को लगातार सीपीसी की श्रेणी में रख रही है। लेकिन अमेरिकी सरकार ने अभी भी पाकिस्तान को सीपीसी घोषित नहीं किया है। इसे उसकी दोहरी नीति कह सकते हैं। समिति ने अमेरिकी सरकार से निवेदन किया है कि पाकिस्तान को सीपीसी श्रेणी में रखा जाए और इस संबंध में पुख्ता कदम उठाने के लिए बाध्य किया जाए। रपट में यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान के मजहबी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाए, ईशनिंदा कानून को समाप्त किया जाए तथा मजहबी सहिष्णुता के लिए एक अभियान चलाया जाए रपट के अनुसार पाकिस्तान में मजहबी अल्पसंख्यकों कों सामाजिक तथा राजनीतिक हाशिए का सामना करना पड़ता है। 342 सीटों वाली नेशनल एसेम्बली में केवल 10 सीटें मजहबी अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध है। वही एसेम्बली के ऊपरी सदन में अल्पसंख्यकों के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं हैं। इस रपट में सऊदी अरब, अफगानिस्तान और कुछ अन्य देशों में भी हिन्दुओं पर हो अत्याचारों को शामिल किया गया है। आशा है, भारत सरकार तथा अन्य संगठन इस रपट पर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे।

संवाद केन्द्र द्वारा महिला पत्रकार की हत्या की भर्सना

55 वर्षीय कन्नड़ महिला पत्रकार लंकेश पत्रिके' की संपादक एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता गौरी लंकेश की जघन्य हत्या पर आक्रोश एवं दुःश व्यक्त करते हुये विश्व संवाद केन्द्र महाकौशल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं महाकौशल – संदेश के सम्पादक डॉ. किशन कछवाहा ने कर्नाटक सरकार से अविलम्ब दोषियों की गिरफतारी एवं उन्हे खिलाफ कड़ी कारवाई करने की मॉग की है। गत दिवस गौरी लंकेश की हत्या उनके ही धर पर कर दी गयी थी। पुलिस इस हत्या के पीछें वैचारिक मतभेद और जमीन – जायजाद के विवाद को प्रमुख कारण मानकर जॉच का आगे बढ़ा रही है। इस दौरान कर्नाटक में इस हत्या को लेकर सियासी दॉव पेंच और अरोप – प्रत्यारोप का भी सिलसिला चल पड़ा है। कर्नाटक सरकार ने इस हत्याकांड की जॉच के लिये एक विशेष टीम एम.आई.टी का भी गठन कर दिया है।

पाकिस्तान मांगने वाले तो यही रह गए

सिंधी,बलूची, पश्तून, पठान, आदि ने तो पाकिस्तान नही मांगा था। यह मांग अलीगढ़, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद,अहमदाबाद मेवात, मेरठ, अहमदनगर के मुसलमानों ने की थी। लेकिन जब इन्हें मु जाहिर कहा जाने लगा तो ये वहां गए ही नही

हामिद अंसारी के मनोविज्ञान को समझाने से पहले कृपया आपको पाकिस्तान के 'मूल निवासियों' से नफरत करना बंद करना होगा। पाकिस्तान के मूल निवासी मतलब सिंधी, बलूची, पश्तून, पठान, पन्जाबी क्योंकि इतिहास गवाह है इनमें से किसी ने भी पाकिस्तान नही मांगा था... तो फिर पाकिस्तान मांगा किसने था ? पाकिस्तान मांगा था अलीगढ़, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदनगर, मेरठ, मेवात के मुसलमानों ने। 40 के दशक में जिन्ना को तन–मन–धन से इन्होने सहारा दिया। लेकिन जब बटबारा हो गया तो पाकिस्तान के मूल निवासी सिंधी, बलूची, पश्तून, पठान, पंजाबी मुसलमान हैरान परेशान हो गये। वे सोचने लगे ये कौन यहां आ गये ?जनाब, अर्ज किया है, फरमाया है . जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करने वाले ये लोग है कौन ? ये तो हमारी भाषा भी नही है ...हम तो सिंधी, बलूची, पंजाबी, पश्तों बोलते हैं और ये लोग तो बात बात परोर सुनाते है। पाकिस्तान के 'मूलनिवासियों' को महसूस होने लगा कि अचकन और शेरवानी पहनने वाले अलीगढ़ ,मेरठ, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, अहमदनगर से आये ये लोग हमारे अपने कैसे हो सकते हैं ? पाकिस्तान बनने के 2–4 साल बाद ही उसके 'मूलनिवासी मुसलमानों' ने इन जहीन उर्दू बोलने और शेर पढ़ने वालों को उनकी औकात दिखा दी। तेजी से यह खबर उन रसूखदार मुसलमानों तक पहुँचाने लगी जो अब तक हिन्दुस्तान में ही रह गये थे। ये'अलीगढ़ सोच' के वे लोग थे जिन्हाने जिन्ना और पाकिस्तान के ख्वाब के लिये सब कुछ किया था।लेकिन1947 की अफरा–तफरी में ये लोग पाकिस्तान नही जाना चाहते थे, सही वक्त के इंतजार में थे। उन्हे यहां अपनी संपत्ति, कई पेन्डिंग काम निपटाने थे। इतिहास गवाह है... उस दौर के प्रोपर्टी ब्रोकर टाइप के लोग पाकिस्तान के हिन्दु और भारत के मुसलमानो की संपत्ति की कीमत कौड़ियों में लगा रहे थे । लेकिन पाकिस्तान के कराची से आया एक शब्द 'मुजाहिर इनके कान में पड़ा तो इन 'अलिगढ़ सोच' वालों की नींद उड़ गई। इनका पाकिस्तान का ख्वाब का चकनाचूर हो गया और इन्होने मजबूरी में दिल पर पत्थर रख कर पाकिस्तान जाने से तौबा कर ली। कभी 14 अगस्त, 1947 के दिन इन 'अलिगढ़ सोच' वालों ने ख्वाब देखा था कि सर रेडक्लिफ मुगलिया सल्तनत के नक्शे के हिसाब से बंटबारा करेंगे जिसमें उत्तर उनका होगा और दक्खिन हिंदुओं का। लेकिन जब 17 अगस्त, 1947 को रेड क्लिफ लाइन का एलान हुआ तो उसमें पाकिस्तान बित्ते भर में सिमट गया। उफ्फ.. मुगलिया दौर की सारी निशानियां, सारी सोच तो यही रह गई और शायद इन्ही में से एक यहां रह गए डॉ. हामिद अंसारी जैसे कुछ लोग

सर्वोच्च न्यायालय का दखल

केरल के लवजिहाद के तेजी से बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेते हुए गत १६ अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को लवजिहाद की तहकीकात करने के आदेश दिये है। इस जांच की निगरानी के लिये न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. रविन्द्रन को नियुक्त किया है । सर्वोच्च न्यायालय ने यह कदम एन.आई.ए के उस खुलासे के बाद उठाया है , जिसमे कहा गया था कि हिन्दु लड़कियों को कन्वर्ट करके मुस्लिम युवकों से शादी कराये जाने का एक चलन देखने में आया है। इस संदर्भ में केरल पुलिस को एन. आई.ए को सभी प्रकार की सहायता देने को कहा गया है । यह मामला तब प्रकाश मे आया जब केरल के सफीनजहां के वकील द्वारा इस संबंध मे एनआईए की पड़ताल के विरोध को सर्वोच्चय न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान मे लिया था। जहा ने दिसम्बर, २०१६ मे एक हिन्दु युवती से निकाह किया था । उसके निकाह को केरल उच्च न्यायालय ने यह कहते हुये निरस्त कर दिया था कि यह देश की महिलाओं की स्वतंत्रता का अपमान है । उच्च न्यायालय ने इसे लव जिहाद की मिसाल बताते हुये राज्य मामलों की पड़ताल करने को कहा था।

जरा सो चिये क्या खा रहे है।

पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित पढ़े–लिखे लोग मूर्खो के लिये बुरी खबर ! मैकडोनल्ड ने अपने कर्मचारियों को चेताया है कि जो फास्टफूड ग्राहकों को परासते है उसे न खाये, क्योकि इसे ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है । एक तरफ मैकडो नल्ड दुनियाभर में लोकलुभावन विज्ञापनों के जरिये लोगों को अपने उत्पादों को खरीदने के लिये लुभाता है दूसरी तरफ अपनी वेबसाइट पर अपने कर्मचारियों के लिये चेतावनी जारी करता है कि वे ज्यादा फास्टफूड खाने से बचे।कंपनी ने 2013 में कर्मचारियों से कहा था कि फास्ट फूड में काफी मात्रा में कैलोरी, वसा शर्करा,इत्यादि मौजूद होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति पर मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। अगर उसके कर्मचारी ज्यादा फास्टफूट खाते है तो वे मोटे हो जायेंगे। कंपनी ने वेबसाइट पर जिन फास्टफूड का नुकसान दायक बताया था उनमें बर्गर, फ्राइज, सोडा आदि शामिल है । वेबसाइट में यह भी कहा गया था कि जिन लोगों को उच्च रक्तचाप, मधु मेह और दिल से संबंधित बीमारियां है, उन्हें फास्टफूड खाते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिये। इससे पहले मैकडोनल्ड के पूर्व सीईओ डॉन थॉम्सन ने एक बैठक के दौरान कंपनी का बचाव करते हुये कहा था कि मै कडोनल्ड जंक फूड की ब्रिकी नही करता। इतना सब होने के वावजूद 'कूल डूड' प्रजाति के लोग नही सु धरेंगे और फास्टफूड खाते रहेंगे!

मंदिर निर्माण के लिये पदयात्रा करेगा मुस्लिम मंच

राष्ट्रीय स्यवंसेवक संघ से संबद्ध मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अयोध्या में आम सहमति से राम मंदिर निर्माण के लक्ष्य को लेकर अगले महिने राजधानी से अयोध्या तक पदयात्रा करेगा। कार्यक्रम के संयोजक महिरध्वज सिंह ने बताया कि हमं अयोध्या में आम सहमति से राम मंदिर निर्माण चाहते है। इसके लिये मंच लखनऊ से अयोध्या पदयात्रा करेगा। करीब 140 कि.मी. की पदयात्रा 11 सितम्बर से शुरू होकर 16 सितम्बर को अयोध्या पहुँचेगी। उन्होने बताया कि पदयात्रा के दौरान लोगों को अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बारे में जागरूक किया जायेगा। अयोध्या के कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार और साधु–संत हिस्सा लेंगे। मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल ने कहा कि उनका संगठन मुस्लिम समुदाय के साथ लगातार बैठके करता आया है और वह उन्हे समझाने की कोशिश करता रहा है कि मंदिर मुद्दे का हल आम सहमति से हो। अफजल ने दावा किया कि मंच को अयोध्या मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय से अनूकूल प्रतिक्रिया की उम्मीद है। गोवध के खिलाफ भी हमारा अभियान भी सफल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को राम मंदिर को संवेदनशील और भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुये सलाह दी थी कि सबसे अच्छी बात यह होती है कि इस मुद्दे का समाधान परस्पर सहमति से हो। अयोध्या पदयात्रा के बारे में मंच की हरिद्वार बैठक के दौरान चर्चा की गई थी। कार्यक्रम का ब्यौरा पूछने पर महिरध्वज ने बताया कि एक या दो दिन में इसे अंतिम रूप दे दिया जायेगा। इस बीच बकरीद से ऐन पहले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मुसलमानों से अपील की है कि वे बकरों की कुर्बानी की बजाय अपनी बुरी आदतों की कुर्बानी दे। मंच के संयोजक अवध प्रान्त सैयद हसन कौसर ने कहा था कि बकरीद पर जानवर की कुर्बानी तीन तलाक की तरह ही बुरी परंपरा है। इस दिन कुर्बानी की वकालत करने वालों का जनता को बहिष्कार करना चाहिये। बकरीद के दौरान कुर्बानी इस्लाम में हराम है और गैर–इस्लामिक है। उन्होने कहा कि यदि कोई कुर्बानी देना चाहता है तो उसे बुरी आदतों की कुर्बानी देनी चाहिये। हसन ने कहा कि जानवर की कुर्बानी को लेकर मुस्लिम समुदाय में कई तरह के अंधविश्वास है, जो बेहतर शिक्षा पाते है, वे ही इस्लाम को समझेंगे। मंच के सह संयोजक केए खुर्शीद आगा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की वकालत करते हुये कहा कि कुरान के मुताबिक किसी विवादित जगह पर नमाज नही पढ़ी जा सकती।

संघ की बैठक में कश्मीर पर चर्चा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठनों की समन्वय बैठक शुक्रवार शुरू हुई जिसमें जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई और समझा जाता है कि इस दौरान घाटी की स्थिति से मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। इस बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत की और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत कई प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि इसमें विभिन्न संगठनों के कामकाज पर चर्चा होगी और समीक्षा की जायेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या राम मंदिर के विषय पर चर्चा होगी, उन्होने कहा कि बैठक में विश्व हिन्दु परिषद भी हिस्सा ले रही है, ऐसे में वे राम मंदिर के विषय पर अपनी बात रख सकते है। आरएसएस की तीन दिवसीय समन्वय बैठक के पहले दिन बैठक को संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी और वरिष्ठ प्रचारक सुरेश सोनी ने संबोधित करते हुये संघ के कार्यो और इस बैठक के महत्व को रेखांकित किया। सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी जी ने कहा, ''हम सभी संगठन भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विचार धारा को लेकर सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे है। बदलते हुये विश्व परिदृश्य, देश की परिस्थिति और अपने संगठन की स्थिति का योग्य आकलन करते हुये हम सभी को अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ना है।'' उन्होने कहा, ''किसी भी नये कार्य को करने में उसके समक्ष–उपेक्षा, विरोध और स्वीकार – यह तीन पडाव होते है। पहले दो पड़ाव पार कर हम समाज में स्वीकृति का अनुभव कर रहे है। लेकिन हम विश्व परिदृश्य, देश की वर्तमान स्थिति का योग्य आकलन कर सके व उसके लिये हम सभी में इसके लिये अपेक्षित समझ हो, इसलिये आने वाले तीन देशों में अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे।'' संघ से जुड़े 40 सहयोगी संगठन की इस समन्वय बैठक की अध्यक्षता मोहन भागवत ने की। राष्टीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय समंवय बैठक की शुरूआत यहां संघ के प्रमुख मोहन भागवत व सर कार्यवाह भैया जी जोशी द्वारा भारत की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पण कर की गई।

पृष्ठ क्रं. 1 का शेष भाग

उमरती जा रही हैं। इन्ही इलाकों में आतंकी पनाह लेते हैं जो पूरे पाकिस्तान की शांति के लिये ही दुश्मन बने हुये हैं। आतंकवाद पनपने का असली कारण यह बढ़ती हुयी जनसंख्या है। क्योंकि जनसंख्या में बढ़ोत्तरी होने से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी सामाजिक कानों में आवश्यकतानुसार सुधार न हो पाना।

विचार – कण

यह धारणा मन में न रखें कि मैं कोई बड़ा कार्यकर्ता हो गया हूँ। बड़प्पन की भावना व्यर्थ है। मेरे बिना कार्य नहीं चलेगा, यह भावना कभी हमारे मन में न आये। संघ संस्थापक की महान अखंड ज्योति के तिरोधान होने पर भी यह कार्य बढ़ता ही जा रहा है। कोई इसकी प्रगति को रोक नहीं सकता। संघ की गति अप्रतिहत है।''

सूचना

कृपया आप ~~अपना ई~~–मेल एवं मोबाइल नम्बर महाकौशल संदेश के ई मेल पर भेजने का कष्ट करें ताकि 'महाकोशल संदेश' आपको ईमेल पर प्रेषित किया जा सके । – सम्पादक

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं–1, म.नं. 1692, नवआदर्श कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने - बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान–विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआदर्श कॉलोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश । संपादक– डॉ. किशन कछवाहा
Email:- vskjbp@gmail.com kishan_kachhwaha@rediffmail.com